परदेस में जयगान से खुशहाली की उम्मीद

आलोक मेहता
वरिष्ठ पत्रकार

न्यूयार्क से बीजिंग तक, पेरिस से सिडनी तक, ब्राजील से टोक्यो तक, काठमांडू से मालदीव तक भारत के लिए जयगान के स्वर सुनाई देना निश्चित रूप से गौरव और प्रसन्नता की बात है. केवल एक वर्ष में अपनी छवि बनाने और भारत के आर्थिक विकास के लिए नए रास्ते बनाने का श्रेय लेना सचमुच आसान काम नहीं है. इसलिए सारी कमजोरियों और समस्याओं के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मविश्वास को समझा जा सकता है. मुख्यमंत्री अथवा पार्टी के पदाधिकारी के रूप में नरेंद्र मोदी कुछ देश की यात्राओं अथवा वायब्रेंट गुजरात के आयोजनों से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की नब्ज थोड़ी पहचान सके होंगे. लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में महाशक्तियों के राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्रियों से सीधें संवाद, आर्थिक संबंधों के समझौते के साथ जटिल कूटनीतिक दांव पेंच की दृष्टि से उनका पहला अनुभव रहा. फिर भी, उन्होंने अपने वाकचातुर्य और गुजराती मार्केटिंग शैली से लोगों को प्रभावित किया. इस सफलता का दूसरा पहलू अमेरिका, चीन, यूरोपीय अथवा एशियाई देशों की अपनी मजबूरियां और भारत से लाभ की संभावनाएं दिखना भी रहा है. चुनावी मंचों अथवा टीवी. कार्यक्रमों में भाजपाई अथवा अन्य पार्टियों के नेता पिछले 68 वर्षों की कई विफलताओं का भले ही कितना उल्लेख करते हों, उसी अवधि में भारत विश्व की दौड़ में पहली पंक्ति में भी पहुंचा है. इसी क्रांति से भारत में एक बड़े बाजार की क्षमता से दुनिया के सौदागर लाभ की अपेक्षाएं अधिक करने लगे हैं. यही नहीं अमेरिका, ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया, जर्मनी जैसे संपन्न देशों में प्रवासी भारतीयों ने अपनी मेहनत और योग्यता से सम्मानजनक स्थान बना लिया है. ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका में तो प्रवासी भारतीयों के वोट की महत्ता सत्ता को बनाने-बिगाड़ने वाली हो गई है. इसलिए भारत की जयकार लगवाने में नरेंद्र मोदी अधिक सफल दिखाई दिए हैं.

पूर्व में की गई आशंकाओं के विपरीत पाकिस्तान, चीन और अमेरिका से रिश्ते अच्छे बनाने के प्रयास मोदी ने किए. यदि केवल नवाज शरीफ के बस में होता तो संभवतः पाकिस्तान से संबंधों में सकारात्मक प्रगति दिखाई देती, लेकिन पाकिस्तानी सेना ओर आईएसआई. के गहरे प्रभाव के कारण यह संभव नहीं हो पाया. चीन के साथ सीमा विवाद जल्द हल होने की उम्मीद भी नहीं की जा सकती. लेकिन

> उपलब्धि के नाम पर नरेंद्र मोदी यह दावा अवश्य कर सकते हैं कि इस एक वर्ष में उनकी सरकार पर घोटालों का कोई गंभीर आरोप नहीं लग सका.

आर्थिक संबंधों में प्रगति और शीर्ष नेताओं में पारस्परिक विश्वास बनना शुभ संकेत है. फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, जापान, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, सिंगापुर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश आर्थिक और व्यापारिक संबंधों के लिए भारत की आरती अवश्य उतारते रहेंगे. हां, मिलियन नहीं बिलियन डॉलर का सवाल यह है कि परदेस में गूंज रही शहनाइयों का फल भारतवासियों को कितना मिल पा रहा है? काला धन विदेश से लाने में देरी लग सकती है, भारत के छोटे बड़े व्यापारियों को पूंजी लगाने तथा अनावश्यक परेशानियों से बचाने में देरी क्यों है?

इस सवाल का जवाब देने में मोदी सरकार के मंत्रियों और पार्टी नेताओं को थोड़ी कठिनाई हो रही है. वे केवल धैर्य से प्रतीक्षा की सलाह ही दे पाते हैं. वास्तविकता यही है कि चीन, अमेरिका, जापान, फ्रांस या कनाडा के साथ अरबों रुपयों की लागत वाले समझौतों को तैयार करना आसान है. उनके क्रियान्वयन में 5 से 10 वर्ष तक लगने वाले हैं. जबकि 2014 के चुनाव में भाजपाई नेताओं और स्वामी रामदेव जैसे अज्ञानी समर्थकों ने भोलीभाली जनता के बीच कुछ हफ्तों-महीनों में चांदी की थाली में दाना-पानी के साथ हरेक के खाते में दस बीस लाख आ जाने का विश्वास दिला दिया था. चांदी के महलों वाले ऐसे सपने बहुत जल्दी टूट गए. सपने टूटने के बाद लोग और अधिक उत्तेजित होकर गली-मोहल्ले में अपनी नाराजगी व्यक्त करने लगे. बड़े पूंजीपति अभी पूंजी लगाने के लिए अपनी परियोजनाएं बनाकर आगे बढ़ने को तैयार हुए, तो भूमि अधिग्रहण कानून के विरोध की आंधी से सत्ता के दरवाजे भड़भड़ाने लगे. इसे 'प्रथम ग्रासे मक्षिका पातः' यानी पहले दौर में ही मख्खी गिरना कहा जा सकता है. भाजपा सरकार को इस कानून पर इतने बड़े बवाल की उम्मीद नहीं थी. अब सत्ता का दूसरा वर्ष शुरू होने से पहले मोदीजी को इस 'काले कानून' को ठंडे बस्ते में डालते हुए अपनी प्रतिष्ठा भी बचाने की कोशिश करनी होगी. तभी देशी-विदेशी पूंजी से प्रगति की गाड़ी आगे बढ़ सकेगी.

उपलब्धि के नाम पर नरेंद्र मोदी यह दावा अवश्य कर सकते हैं कि इस एक वर्ष में उनकी सरकार पर घोटालों का कोई गंभीर आरोप नहीं लग सका. मनमोहन सिंह राज के अंतिम दौर में निकम्मेपन और भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा दिख रही थी. जाते-जाते मनमोहन सिंह यह दावा भी कर गए थे कि 'इतिहास हमारे काम को याद करेगा.' सचमुच घोटालों का वह अध्याय इतिहास में से कैसे मिट पाएगा? बहरहाल, मोदी सरकार के कुछ मंत्री अनुभवी और सक्षम हैं तो कुछ अनाड़ी और खिलाड़ी भी. मोदी की टीम की असली परीक्षा अब शुरू होगी. अरुण जेटली और नितिन गडकरी अपने अनुभवों और संपर्कों से आर्थिक क्षेत्र में तेजी लाने का प्रयास कर सकते हैं. सुषमा स्वराज, प्रकाश जावडेकर, मनमोहन पार्रिकर जैसे मंत्रियों की ईमानदारी और कार्य क्षमता का लाभ मिल सकता है. लेकिन निर्मला सीतारमण, स्मृति ईरानी, उमा भारती के मंत्रालयों के कामकाज पर विरोधी से अधिक संघ-भाजपा के प्रबल समर्थक तक आंसू बहा रहे हैं.

प्रधानमंत्री सचिवालय द्वारा कामकाज की निरंतर समीक्षा तथा सलाह मशविरे के बावजूद विभिन्न मंत्रालयों में निर्णय महीनों से अटके पड़े हैं. छोटी-छोटी समितियों, सामान्य नियुक्तियों में भी मंत्री स्वयं फैसला करने में डरते हैं, क्योंकि उन्हें बाद में प्रधानमंत्री से फटकार का खतरा लगता है. यदि प्रधानमंत्री हर खतरे को उठाने को तैयार हैं, तो उनके मंत्री अपने कायरतापूर्ण व्यवहार से सरकार की गाड़ी दलदल में क्यों फंसा रहे हैं? ऐसी स्थिति में नरेंद्र मोदी को अंतरराष्ट्रीय छवि से अधिक देश में जनता की मूलभूत आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए मंत्रिमंडल की समीक्षा करनी होगी. चुनौतियों का पहाड़ सामने है.

महंगाई, बेरोजगारी गांव-कस्बों में किसानों की समस्या सुलझाने के लिए आत्मविश्वास के साथ एक सक्षम ईमानदार टीम सरकार के लिए जरूरी है. सांसदों या पार्टीजनों के हर सुझाव या सिफारिश में निहित स्वार्थ तथा भ्रष्टाचार की गंध ढूंढ़ना भी अनुचित है.

विदेशी चंदे से हेराफेरी करने वाले एनजीओ को सजा दी जाए, लेकिन सही अर्थों में सेवा करने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग राजनीतिक दलों से ज्यादा उपयोगी साबित हो सकता है. एक साल के दौरान धर्म के तथाकथित ठेकेदार नेताओं और कुछ संगठनों ने न केवल मोदी सरकार वरन भारत की छवि पर कालिख लगाने के प्रयास किए. अनर्गल बयानों और हिंसक गतिविधियों से देश बदनाम भी हुआ. इसलिए आत्ममंथन के दौर में ऐसे तत्वों पर कड़ी कार्रवाई किए बिना भारत का जयगान अधिक समय तक परदेस में सुनाई नहीं देगा.

सुषमा का कद घटा

अपनी विशिष्ट वक्तृत्व शैली के लिए मशहूर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज केंद्रीय मंत्रिमंडल की वरिष्ठतम सदस्यों और भाजपा की सबसे असरदार नेताओं में से एक हैं. राजग सरकार के एक साल के कार्यकाल में बतौर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को कोई अहमियत नहीं दी जाती. प्रधानमंत्री अपने विदेश दौरों में अक्सर श्रीमती स्वराज को नहीं ले जाते और न ही नीतिगत मसलों पर उनसे सलाह करते हैं. आलम यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को

> श्रीमती स्वराज को मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति से भी बाहर रखा गया है. सुषमा को महत्वपूर्ण देशों की यात्रा पर प्रधानमंत्री अपने साथ नहीं ले जाते.

जिन देशों की यात्रा करनी होती है, वहां तैनात भारतीय राजदूतों से सीधी बातचीत कर वह खुद रणनीति बना लेते हैं. ईरान के साथ हाल ही में छबहार बंदरगाह पर भारत ने समझौता किया. सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस समझौते को अंतिम रूप देने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की जगह प्रधानमंत्री ने सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को भेजा.

श्रीमती सुषमा का कद विदेश सचिव पद से सुजाता सिंह को अचानक हटाने के साथ घटना शुरू हुआ. प्रधानमंत्री ने अमेरिका में तत्कालीन राजदूत एस. जयशंकर को नया विदेश सचिव बना दिया. श्रीमती स्वराज को मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति से भी बाहर रखा गया है. सुषमा को महत्वपूर्ण देशों की यात्रा पर प्रधानमंत्री अपने साथ नहीं ले जाते. जिन देशों में वह प्रधानमंत्री के साथ गईं, वहां यह सुनिश्चित किया गया कि उन्हें ज्यादा महत्व न मिले. उन्हें ऐसे देशों की यात्रा पर भेजा जाता है, जो कूटनीतिक संबंधों के लिहाज से भारत के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होते. फिलहाल सुषमा स्वराज फाइलों पर हस्ताक्षर करने तक ही सिमटी हुई बताई जाती हैं. विदेश मंत्री पद का महत्व घटा देने से विपक्ष मोदी सरकार पर हमला करने का कोई मौका नहीं चूकता.

उपलब्धियां कम विवाद ज्यादा

हर्षवर्धन आर्य
निवासी संपादक, लोकमत समाचार

विवादों में मंत्री

मोदी सरकार के कई मंत्री अपने बयानों, भ्रष्टाचार के आरोपों और फैसलों को लेकर विवादों में आए.

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने नई सरकार के सत्ता संभालने के तीन हफ्ते के भीतर ही कह दिया कि जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. इसका तगड़ा विरोध हुआ और मोदी सरकार को सफाई देनी पड़ी.

केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी अपनी शैक्षणिक योग्यता के कारण विवादों में रहीं. उनके चुनावी हलफनामों तथा केंद्रीय मंत्री पद ग्रहण करने के बाद दी गई आधिकारिक जानकारी में शैक्षणिक योग्यता अलग-अलग बताई गई. 2004 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने खुद को पत्राचार पाठ्यक्रम के जरिए स्नातक (बी.ए.) बताया था. 2014 के लोकसभा चुनाव में ईरानी ने खुद को दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में बीकॉम पार्ट-1 तक शिक्षित घोषित किया. बाद में उन्होंने खुद को येल विश्वविद्यालय से शिक्षित बताया था.

मोदी सरकार में घोर उपेक्षा का सामना कर रहीं विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने 'गीता' पर बयान देकर बखेड़ा कर दिया था. गत वर्ष उन्होंने एक समारोह में कहा कि श्रीमद् भगवत गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाना चाहिए. मोदी सरकार के एक और मंत्री निहालचंद मेघवाल 16 अन्य लोगों के साथ राजस्थान में बलात्कार के एक मुकदमे में अभियुक्त हैं. उन पर जयपुर की एक विवाहिता के साथ बलात्कार करने का आरोप है.

मोदी सरकार में अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री नजमा हेपतुल्लाह मुस्लिम आरक्षण तथा देश के सभी मुसलमानों को कथित रूप से हिंदू करार देने पर विवादों में आ गईं थीं. उन्होंने कहा था कि मुसलमानों को आरक्षण देने से उनकी समस्याएं हल नहीं होंगी और न ही हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की इजाजत देता है. पश्चिम बंगाल में उन्होंने भारत के सभी मुसलमानों को कथित रूप से हिंदू कहकर खुद को मुसीबत में फंसा लिया था. बाद में उन्होंने सफाई दी थी कि उनका आशय हिंदुस्तानी से था.

केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी इन दिनों 'पूर्ति' कंपनी को कथित रूप से गलत तरीके से ऋण दिलवाने तथा उसकी पूरी अदायगी न करने के मसले पर घिरे हुए हैं. 'कैग' की रिपोर्ट में गडकरी को कठघरे में खड़ा किया गया है. भाजपा अध्यक्ष के रूप में भी 'पूर्ति' को लेकर गडकरी विवादों में रहे तथा उन्हें भाजपा अध्यक्ष का पद गंवाना पड़ा था.

दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने एक सभा में भाषण दे दिया कि जनता को तय करना है कि उन्हें रामजादों की सरकार चाहिए या हरामजादों की. मोदी सरकार को संसद में माफी मांगनी पड़ी थी.

लोकसभा चुनाव के दौरान गिरिराज सिंह ने एक सभा में टिप्पणी कर विवाद पैदा कर दिया था. जो लोग नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने से रोकना चाहते हैं, उनके लिए भारत में कोई स्थान नहीं है. ऐसे लोगों की जगह पाकिस्तान में है. हाल ही में केंद्रीय मंत्री के रूप में उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर नस्लवादी टिप्पणी कर मोदी सरकार की मुसीबत बढ़ा दी. लोकसभा में उन्हें माफी मांगनी पड़ी और प्रधानमंत्री ने उन्हें जमकर फटकारा भी.

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री हरिभाई चौधरी ने संसद में मुंबई बम कांड के मुख्य आरोपी दाऊद इब्राहिम के बारे में विवादास्पद बयान देकर मोदी सरकार को परेशानी में डाल दिया. चौधरी ने कहा कि सरकार के पास दाऊद का पता-ठिकाना नहीं है. चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी सत्ता में आते ही दाऊद को गिरफ्तार करने का वादा जनता से कर रहे थे. चौधरी के बयान पर संसद में सरकार की काफी किरकिरी हुई और विपक्ष को हावी होने का मौका मिल गया.

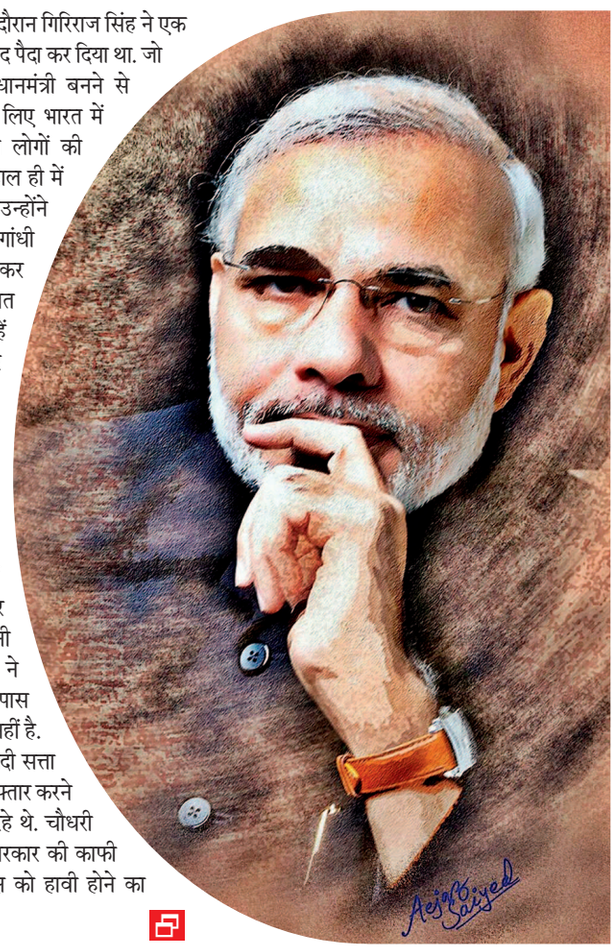

डॉ. हर्षवर्धन की स्वास्थ्य मंत्रालय से विदाई

दिल्ली में लोकसभा चुनाव तक भाजपा का चेहरा रहे डॉ. हर्षवर्धन को मोदी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में शामिल किया गया था, लेकिन छह माह के भीतर ही उनका विभाग बदल दिया गया. उनकी जगह वरिष्ठ भाजपा सांसद जे.पी.नड्डा को स्वास्थ्य मंत्रालय सौंप दिया गया. पेशे से चिकित्सक तथा दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में उत्कृष्ट कार्य कर चुके डॉ. हर्षवर्धन की उनके प्रिय मंत्रालय से विदाई ने विवादों को जन्म दे दिया. बताया जाता है कि दिल्ली के एम्स के मुख्य सतर्कता अधिकारी संजीव चतुर्वेदी को पद से हटाने के मामले में डॉ. हर्षवर्धन की कुर्सी गई. ईमानदार अफसर के रूप में चर्चित चतुर्वेदी ने एक घोटाले में नड्डा के करीबी अफसर सहित कुछ अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई जांच की सिफारिश की थी. आरएसएस एवं मोदी के करीबी नड्डा ने हर्षवर्धन को पत्र लिखकर चतुर्वेदी को हटाने के लिए दबाव डाला था. इस विवाद में हर्षवर्धन पर नड्डा भारी पड़े.

जशोदाबेन की आरटीआई

पिछले एक वर्ष से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पत्नी जशोदाबेन को लेकर काफी विवादों में रहे. लोकसभा चुनाव में मोदी ने पहली बार हलफनामे में जशोदाबेन का पत्नी के रूप में उल्लेख किया. इसके पूर्व उन्होंने किसी भी विधानसभा चुनाव या अन्य किसी मंच पर जशोदाबेन का जिक्र पत्नी के रूप में नहीं किया था. मामला हलफनामे के साथ ही खत्म नहीं हुआ. जशोदाबेन को शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित न करने तथा दिल्ली में साथ में न रखने पर भी मोदी चर्चाओं में रहे. इसके बाद अपनी पत्नी के सूचना अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी ने प्रधानमंत्री के साथ-साथ सरकारी मशीनरी के माथे पर बल ला दिए. जशोदाबेन ने सूचना के अधिकार कानून के तहत पूछा था कि प्रधानमंत्री की पत्नी की सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में क्या मापदंड अपनाए जाते हैं. उनकी अपील अब गुजरात उच्च न्यायालय के दरवाजे पर है. विपक्ष जशोदाबेन के मामले को लेकर मोदी को निशाना बनाता रहा है और प्रधानमंत्री ने अब तक अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है.

मोदी का नुस्खा...

मेक इन इंडिया

नरेंद्र मोदी का यह बहुत बड़ा सपना है. जिस तरह से आज दुनिया भर में मेड इन चाइना की धूम मची है, उसी तर्ज पर पिछले साल सितंबर में शुरू किए गए इस अभियान का अभी शुरुआती चरण है. इतनी जल्दी आकलन नहीं किया जा सकता कि सफलता की ओर कितना बढ़े हैं.

जन धन योजना

पिछले साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जन धन योजना की शुरुआत हुई थी. लक्ष्य है कि हर व्यक्ति का बैंक अकाउंट जरूर हो. इसके लिए जीरो बैलेंस की सुविधा दी गई है. इस योजना का असर दिखने लगा है. 12 करोड़ अकाउंट खोले जा चुके हैं और 10 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा जमा हो चुके हैं.

स्वच्छ भारत अभियान

मोदी का सपना है कि महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती तक देश पूरी तरह साफ-सुथरा हो जाए. इसके लिए खूब विज्ञापन भी हो रहे हैं. खूब बातें भी हो रही हैं लेकिन तस्वीर तभी बदलेगी, जब आम आदमी सफाई के प्रति जागरूक हो. शहरों में सार्वजनिक सुविधाओं की कमी सबसे बड़ा रोड़ा है.

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ

काश! यह सपना पूरा हो जाए! मोदी ने कोई पहली बार यह सपना नहीं देखा है. इसके पहले की सरकारें भी कागजों पर इस सपने को उतारती रही हैं. बोर्ड बनते रहे हैं, विज्ञापन होते रहे हैं लेकिन हालात नहीं सुधरे. मोदी राज में भी नहीं!

कौशल विकास

युवाओं में कौशल विकास के लिए 73 से अधिक कौशल विकास योजनाएं हैं. ये सभी योजनाएं पहले से चल रही हैं. 2013-14 में लक्ष्य की तुलना में सफलता रही 104 प्रतिशत. 76 लाख से अधिक युवाओं को स्किल्ड बनाया गया.

स्मार्ट सिटी

स्मार्ट सिटी तैयार करने की दिशा में कागजी कार्रवाई शुरू हुई है लेकिन सामान्य लोगों के सामने अभी भी पूरी तस्वीर स्पष्ट नहीं है कि कोई शहर कैसे स्मार्ट बन जाएगा. जब तक कोई एक शहर स्मार्ट नहीं बनेगा, तब तक लोगों की जिज्ञासा बनी रहेगी.

कुछ तो गलतियां ढूंढ़ेंगे ही...

गौरीशंकर राजहंस
पूर्व सांसद एवं पूर्व राजदूत

बहुत शीघ्र मोदी सरकार का एक साल पूरा हो जाएगा. अतः यह स्वाभाविक ही है कि इस एक साल की अवधि की सफलता और असफलताओं का विश्लेषण किया जाए. मनुष्य का यह स्वभाव है कि यदि जो व्यक्ति रचनात्मक दृष्टिकोण रखते हैं वे कहते हैं कि गिलास में कम-से-कम आधा गिलास पानी है उससे प्यास कुछ तो बुझेगी और जो बेवजह आलोचनात्मक दृष्टि रखते हैं वे कहते हैं कि बड़ी उम्मीद की थी कि पूरे गिलास में पानी भरकर आएगा. यह तो आधा गिलास खाली है. इसलिए कहने का अर्थ है कि आलोचना करने वाले क्षिद्रान्वेशी हर चीज में कोई-न-कोई नुक्स देखते ही रहेंगे. परंतु यदि निष्पक्ष रूप से विश्लेषण किया जाए तो यह मानना होगा कि गत 30 वर्षों में जितनी सरकारें आईं उनकी तुलना में नरेंद्र मोदी की सरकार सर्वोत्तम है.

एक साधारण परिवार का व्यक्ति जिसने अपना बचपन रेलवे प्लेटफार्म पर और रेल के डिब्बों में चाय बेचकर बिताया वह एक सशक्त नेता होकर उभरे इससे बढ़कर आश्चर्य की बात और क्या हो सकती है? नरेंद्र मोदी के उदाहरण ने सारी दुनिया को यह दिखा दिया है कि भारत में सही अर्थ में लोकतंत्र है. जहां पर एक झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति भी देश के सर्वोच्च पद पर पहुंच सकता है. यह तो मानना ही होगा कि गत 10 वर्षों में संप्रग सरकार जो कई पार्टियों की मिलीजुली सरकार थी इस खिंचातानी से गुजरी थी कि लोग उस कमजोर सरकार से तंग आ गए थे और चाह रहे थे कि केंद्र में कोई मजबूत सरकार हो.

> एक साधारण परिवार का व्यक्ति जिसने अपना बचपन रेलवे प्लेटफार्म पर और रेल के डिब्बों में चाय बेचकर बिताया वह एक सशक्त नेता होकर उभरे इससे बढ़कर आश्चर्य की बात और क्या हो सकती है?

एक मजबूत व्यक्ति देश का नेता हो जो दूरदर्शी हो और जिसके हृदय में केवल आम जनता के कल्याण की भावना हो. नरेंद्र मोदी उस सशक्त नेता के रूप में उभर कर सामने आए और एक साल की अवधि के दौरान भारत ही नहीं विदेशियों ने भी देखा कि भारत एक सक्षम नेतृत्व से संपन्न है और उसका भविष्य अत्यंत ही उज्ज्वल है.

नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री हुए थे तब लोगों को ऐसा लगता है कि विदेशी मामलों में उन्हें कोई अनुभव नहीं है. परंतु दूरदर्शी नरेंद्र मोदी ने एक झटके में ही संसार को दिखा दिया कि विदेशों से मधुर संबंध बनाने में वे जितने माहिर हैं उसके पहले कोई दूसरे प्रधानमंत्री या नेता नहीं थे.

नेपाल के साथ गत 10 वर्षों से भारत के संबंध मधुर नहीं चल रहे थे. यही नहीं चीन बुरी तरह नेपाल पर हावी हो रहा था. नरेंद्र मोदी ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में नेपाल के प्रधानमंत्री सुशील कोइराला को अत्यधिक सम्मान दिया. जब वे पशुपतिनाथ के दर्शन करने नेपाल गए तो नेपाल की जनता में अभूतपूर्व उत्साह देखा गया. सबसे बड़ी बात यह हुई कि जब नेपाल में भूकंप आया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबसे पहले भारत का राहत दल सेना के अफसरों, जवानों, डॉक्टरों के साथ पहुंचा और हवाई तथा सड़क मार्ग से भूकंप पीड़ितों की भरपूर मदद की गई.

नरेंद्र मोदी पर यह गलत इल्जाम लगाया जाता है कि उनकी सरकार 'सूटबूट की सरकार' है. असल में उनकी सरकार जनता की सरकार है. उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान, 'मेक इन इंडिया', 'आदर्श ग्राम योजना' और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े अनेक कार्यक्रमों से जनता में यह छाप छोड़ी है कि देश बदल रहा है और वे जी जान से आम जनता के कल्याण में जुट जाएंगे. सबसे बड़ी बात तो यह हुई कि गत एक वर्ष में कोई बड़ा घोटाला सामने नहीं आया.

स्वच्छ भारत अभियान के तहत एक बात तो अवश्य हुई कि गांव-गांव में अनेक शौचालय बनाए गए जिससे लोगों को खुले में शौच करने की आवश्यकता नहीं हुई. नरेंद्र मोदी ने अपने सांसदों से कहा कि वे सांसद निधि की रकम कम-से-कम दो वर्षों तक गांवों में शौचालय बनाने में खर्च करें.

अंत में बात वहीं आती है जहां से आरंभ हुई थी. जन-धन योजना, बीमा योजना या पेंशन योजना जनता के कल्याण के लिए हैं. अमीरों के लिए नहीं. अमेरिका, कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और चीन में जिस तरह नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत हुआ उससे हर भारतवासी का सिर गर्व से ऊंचा हो गया है.